

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3099
दिनांक 07 अगस्त 2025

खुदरा दुकानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधाएँ

+3099. श्री पी. पी. चौधरी:
श्री दुलू महतो:
डॉ. हेमांग जोशी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2014 से लेकर अब तक विशेषकर राजस्थान राज्य में, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा खुदरा दुकानों पर मुहैया कराए गए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) खुदरा दुकानों पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ओएमसी की भविष्य की योजनाएँ क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशनों के शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई नीति बना रही है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) वर्ष 2014 से देश भर में तथा राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (पीएसयू ओएमसीज) द्वारा स्थापित किए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों (ईवीसीज) के वर्ष-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) ओएमसीज ने बताया है कि तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) पर ईवीसीएस की शुरुआत करना नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) से (ङ) विद्युत मंत्रालय ने सोलर आवर्स के दौरान ईवी चार्जिंग को प्रोत्साहित करने तथा पीक आवर्स के समय इसका उपयोग कम करने हेतु सितंबर 2024 में "एलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर-2024 की स्थापना एवं प्रचालन हेतु दिशानिर्देश" जारी किए हैं, जिसमें 31 मार्च, 2028 तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) के एक भाग के रूप में प्रशुल्क की सीमा निर्धारण का सुझाव दिया गया है, जिसमें सोलर आवर्स के दौरान 30% की छूट तथा पीक आवर्स के दौरान 30% का अधिभार शामिल है।

अनुलग्नक

दिनांक 07.08.2025 को श्री पी. पी. चौधरी, श्री दुलु महतो, डॉ. हेमांग जोशी द्वारा "खुदरा दुकानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधाएँ" के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3099 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन										
	2018-19 से पहले	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (जून, 25 तक)	कुल
राजस्थान	0	9	22	47	201	314	622	681	51	1947
अखिल भारतीय	0	34	65	314	2344	4658	7649	11246	881	27191